Clubs in Madhya Pradesh for training young boys and girls of the State; and

(b) if so, the steps taken by Government in the matter so far?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur): (a) and (b). Two Flying Clubs are already established in Madhya Pradesh, *viz.* Madhya Pradesh Flying Club, Indore; and Nagpur Flying Club, Nagpur. In addition, the establishment of a Flying-*cum*-Gliding Club at Raipur was agreed to, in principle, in August 1961. Two gliders and a Winch have been given to the Club on loan, its instructional, engineering and operational staff have been approved by the Director General of Civil Aviation and it has started gliding training from May, 1965. This club has been included in the Gliding Subsidy Scheme and will receive subsidy/subvention at the prescribed rates.

Further, the Club has purchased a trainer aircraft from the Bombay Flying Club and the appointment of an Engineer for power flying has been approved by the Director General of Civil Aviation. It is expected that the Club will commence power flying training in the near future.

12.05 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

ESTABLISHMENT OF MILITARY BASES IN INDIAN OCEAN BY U.K.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर वैदेशिक-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :-

"हिन्द महासागर में यूनाइटड किंगडम द्वारा सैनिक अड्डे बनाने का प्रस्ताव।"

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : हिंद महासागर में ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकारों को रक्षात्मक सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने एक नई बस्ती की स्थापना का निर्णय किया है जिस का नाम "ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरीटरी" होगा। इस नयी बस्ती को स्थापित करने के लिए ब्रिटेन सरकार ने ऐसे कुछ द्वीप समूहों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है जिन की प्रबन्ध-व्यवस्था इस समय मारिशस और सैलेचेलीज की सरकारें करती हैं और दोनों ही ब्रिटिश उपनिवेश हैं। इस नई बस्ती के लिये जो द्वीप समूह लिए गए हैं उन में मुख्य मोरिशस के 1200 मील उत्तर-पूर्व में स्थित चैगोस द्वीप समूह और सैचेलीज के निकटवर्ती कुछ अन्य छोटे-छोटे द्वीप समूह हैं।

ब्रिटेन के उपनिवेश मंत्री के अनुसार, "मंशा यह है कि ये द्वीप समूह ब्रिटेन और संयुक्त राज्य की सरकारों द्वारा रक्षात्मक सुविधायें तैयार करने के लिए उपलब्ध होंगे किन्तु दोनों में से किसी भी सरकार ने अभी कोई पक्की योजनायें नहीं बनाई हैं। इस के लिये समुचित मुआवजा दिया जाएगा।"

इन द्वीप समूहों को लेने के लिये मारिशस और सैचेलीज की सरकारों को कुछ मुआवजा तो दिया जाएगा, लेकिन कितना, यह अभी निश्चय होना है।

ऐसा मालूम पड़ता है कि ब्रिटेन सरकार ने 1966 में मारिशस को स्वतन्त्रता प्रदान करने की बात को ध्यान में रखकर ये प्रबन्ध किए हैं।

हिंद महासागर में अड्डे स्थापित करने के विषय में भारत सरकार की नीति यही है कि वह इस के सख्त खिलाफ है, और ब्रिटेन सरकार इस बात को जानती है।

उपनिवेशी देश द्वारा अधिशासित प्रदेश का एक भाग रख कर बाकी को छोड़ देने

का विचार आज की विचार-धारा के प्रतिकूल और संयुक्त राष्ट्र के उपनिवेश प्रदेशों को स्वतन्त्रता प्रदान करने के प्रस्ताव के विरुद्ध है ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या ब्रिटेन ने यह नया सुझाव इसलिए अपनाया है कि अदन में ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर आघात हो रहा है और वहां से उन को लग रहा है कि भागना पड़ेगा और क्या मारीशस की आजादी के लिए यह द्वीपों को देना उन्होंने एक शर्त बनाई है और कहा है कि अगर यह द्वीप आप नहीं देंगे तो आप को आजादी नहीं मिलेगी? इन द्वीपों पर सार्वभौमिकता किन की रहेगी, अंग्रेजों की रहेगी या मारीशस आदि की रहेगी, यह मैं जानना चाहता हूं ।

श्री दिनेश सिंह : यह हमारे लिये कहना मुश्किल है कि ब्रिटिश सरकार ने मारीशस सरकार से यह शर्त रक्खी थी या नहीं रक्खी थी। यह बात तो उन दोनों सरकारों के लोगों को ही मालूम होगी ।

श्री मधु लिमये : क्या आप का कोई प्रतिनिधि वहां है नहीं ? मारीशस के लोगों के पुरखे और हमारे पुरखे एक थे ।

श्री दिनेश सिंह : इस बातचीत में हमारा प्रतिनिधि नहीं था लेकिन यह जाहिर है कि चूंकि मारीशस की आजादी 1966 में होने वाली है तो इसलिए ब्रिटेन सरकार ने इन द्वीपों को अलग किया है । बाकी यह शर्त उन्होंने खास रक्खी है या नहीं रक्खी है यह कहना मेरे लिए संभव नहीं है ।

श्री मधु लिमये : दूसरी बात मैं ने यह पूछी थी कि सार्वभौमिकता किस की रहेगी इन द्वीपों पर ?

श्री दिनेश सिंह : जो अभी तक प्रस्ताव ब्रिटेन सरकार ने जाहिर किया है उस से तो मालूम होता है कि यह ब्रिटेन के कब्जे में रहेगा ।

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): May I know if in accordance with the practice which has been prevailing in the UK Government, especially the UK Government in the hands of the Labour Party, this base will not be used, directly or indirectly, for giving encouragement to Pakistani fascism? Has the Government made any enquiry on this point from the UK Government?

Shri Dinesh Singh: I do not think this base will be used for giving any direct facilities to Pakistan against us. Because the Pakstan's borders are adjoining ours and they can do whatever they like directly. But as they are going to be defence bases, Pakistan as a member of the defence pacts may get some assistance from there. Even so, we are opposed to the setting up of foreign military bases in the Indian Ocean.

Shri N. C. Chatterjee (Burdwan): Is it correct that the military base plan is behind the British offer to lend 3 million to Indian Ocean island of Diego Garcia near Mauritius and has that island some strategic significance for US?

Shri Dinesh Singh: This £3 million offer that the hon. Member has referred to is the compensation which is being proposed by the British Government to Mauritius for the establishment of Chagos base. So far as its strategic position is concerned, of course it occupies a very strategic place.

12.09 hrs.

Re: CALLING ATTENTION NOTICE
(Query)

Mr. Speaker: I have received another Calling Attention Notice today from a large number of hon. Members about the serious situation in the Banaras Hindu University.